[श्री धूलश्वर मीणा]

पानी को रोक रही है। इसके लिये राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर लिखकर सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को इस प्रकार की योजनायें बनाने की स्वीकृति न दे। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री और हमारे मुख्य-मंत्री इस बारे में आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं निवदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के बांध बांधने की स्वीकृति न दे और मध्य प्रदेश सरकार को हिदायत दे दे। इसके कारण हमारी महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्दर पानी की कमी हो गई है जिससे बिजली कम पैदा हो रही है, सिंचाई के लिये कम पानी मिल रहा है। इस कारण से राजस्थान चारों तरफ से दिक्कत में जा रहा है। अभी-अभी राजस्थान कैनाल के झगड़े को लेकर पंजाब की नदियों से जो मिलने वाला पानी था उसमें विवाद उठ खड़ा हुआ है। मैं सरकार का ध्यान आपकी मार्फत इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का पश्चिमी एरिया वैसे ही रेगिस्तान है और अगर उसे राजस्थान कैनाल से पानी मिलना बन्द हो जायेगा और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार सारा पानी बन्द कर देगी तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जायेगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और मध्य प्रदेश को इस बारे में हिदायत दे।

REFERENCE TO THE REPORTED LARUS SCALE RETRENCHMENT CV WORKERS IN ANDHRA PRADESH

SHRI KRISHNA MOHAN BHAMI-DIPAir (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairrfaf, Sir, a serious situation has ari-•s&n in /ndhra Pradesh where five lakhs of workers have been rendered jobless due to the freezing of funds by the State Gov-ernment. The rscent order of the State Government issued to the various departments not to release any grants, both budgetary arid non-budgetary, has resulted in the non-implementatio,n of developmental works, including the 20-point economic programme and works relating to canal irrigation, PWD and other works. So a situation has arisen Vhere most of the five lakhs of workers engaged in construction work with contractors have lost their jobs. And the district authorities are not in a position to release grants even for the drought relief works, as also for providing water in the villages affected by the Water problem. Funds earmarked for the 20-point economic programme of the Prime Minister have also been frozen and no developmental activity under the 20-point economic programme is going on in the State. The very fact that the State Government has resorted to directing the management of the T.T.D. to deposit its funds in the treasury and frozen all the funds earmarked by the Central Government for the 20-point economic programme clearly shows that the State is in a state of bankruptcy and it is in financial crisis. 1 think the time has come, an unpleasant duty has come, for the Central Government to intervene.

REFERENCE TO THE INADEQUATE SUPPLY OF FOOD GRAINS TO BIHAR BY THE CENTRE

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : मैं सरकार का ध्यान बिहार की खाद्यान्न स्थिति के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार को प्रति मास एक लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता है और जबकि बिहार को केन्द्र से 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 15 हजार मीट्रिक टन चावल मिला करता है। महोदय, आप यह भी जानते हैं कि बिहार एक अभावग्रस्त राज्य है। तीन साल से लगातार वहां पर बिहार में अकाल और सूखे की स्थिति है। हर